

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

[प्राधिकार से प्रकाशित]

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 370] नई दिल्ली, मंगलवार, तिथि 16, 1975/भाद्र 25, 1897

No. 370] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 16, 1975/BHADRA 25, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Irrigation)

NOTIFICATIONS

*New Delhi, the 16th September, 1975*

S.O. 518(E).—Whereas a vacancy has occurred in the Krishna Water Disputes Tribunal, constituted by the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Irrigation and Power S.O. No. 1419, dated the 10th April, 1969, consequent on the demise of Shri Justice Shamsheer Bahadur;

And whereas the Chief Justice of India has nominated Shri Justice Dibyendu Mohan Sen of the Gauhati High Court to fill the said vacancy under section 5A of the Inter-State Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 4, read with section 5A of the said Act, the Central Government hereby makes the following amendment in the said notification, namely:—

In the said notification under the heading 'Members', for item (ii), the following item shall be substituted, namely:—

"(ii) Shri Justice Dibyendu Mohan Sen, Judge of the Gauhati High Court."

[No. 2(22)/75-WD]

## कृषि और सिंचाई मन्त्रालय

(सिंचाई विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1975

का० आ० 518(अ) भारत सरकार के भूतपूर्व सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय की अधिसूचना का० आ० सं० 1419, तारीख 10 अप्रैल, 1969 द्वारा गठित कृष्णा जल विवाद अधिकरण में न्यायमूर्ति श्री शमशेर बहादुर की मृत्यु के परिणामस्वरूप एक रिक्ति हो गई है;

और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने अन्तर्राष्ट्रिय जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) की धारा 5क के अधीन उक्त रिक्ति को भरने के लिए गौहाटी उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री दिव्येन्दु मोहन सेन को नाम निर्देशित किया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 5क के साथ पठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, 'सदस्य' शीर्षक के अन्तर्गत, संद (2) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(2) न्यायमूर्ति श्री दिव्येन्दु मोहन सेन, न्यायाधीश, गौहाटी उच्च न्यायालय।”

[सं० 2(22)/75-डब्ल्यू० डी०]

**S.O. 519(E).**—Whereas a vacancy has occurred in the Godavari Water Disputes Tribunal, constituted by the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Irrigation and Power S.O. 1421, dated the 10th April, 1969, consequent on the demise of Shri Justice Shamsher Bahadur;

And whereas the Chief Justice of India has nominated Shri Justice Dibyendu Mohan Sen of the Gauhati High Court to fill the said vacancy under section 5A of the Inter-State Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 4, read with section 5A of the said act, the Central Government hereby makes the following amendment in the said notification namely:—

In the said notification, under the heading “Members” for item (ii), the following item shall be substituted, namely:—

“(ii) Shri Justice Dibyendu Mohan Sen, Judge of the Gauhati High Court.”

By order and in the name of the President of India.

[No. 2(22)/75-WD]

S. N. GUPTA, Jt. Secy.

का० आ० 519(अ).—भारत सरकार के भूतपूर्व सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 1421, तारीख 10 अप्रैल, 1969 द्वारा गठित गोदावरी जल विवाद अधिकरण में न्यायमूर्ति श्री शमशेर बहादुर की मृत्यु के परिणामस्वरूप एक रिक्ति हो गई है;

और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने अन्तर्राष्ट्रिय जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) की धारा 5क के अधीन उक्त रिक्ति को भरने के लिए गौहाटी उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री दिव्येन्दु मोहन सेन को नाम निर्देशित किया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 5क के साथ पठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, 'सदस्य' शीर्षक के अन्तर्गत, मद (2) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(ii) न्यायमूर्ति श्री विव्येन्दु मोहन सेन, न्यायाधीश, गौहाटी उच्च न्यायालय।”

राष्ट्रपति के आदेश से और उनके नाम में।

[सं० 2(22)/75-डब्ल्यू० डी०]

सत्येन्द्र नाथ गुप्ता, संयुक्त सचिव ।

